

मूल हिंदी

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं0 2944  
05 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

izèkuea=h vkokl ;kstuk ds varxZr miyfCè;ka

2944- Jh jktsUnz /ksM~;k xkfor%

D;k vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k izèkuea=h vkokl ;kstuk ds varxZr ljdkj us egkjk"V<sup>a</sup> esa  
iky?kj esa 'kgjh {ks=ksa esa vius y{; dks izklr dj fy;k gS( vkSj

¼[k½ ;fn gka] rks bl ;kstuk ds varxZr vkokl ikus okys  
ykHkkfFkZ;ksa dh ftys&okj la[;k fdruh gS\

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) {पीएमएवाई(यू)} के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मांग सर्वेक्षण आकलन करना और स्कीम के तहत शामिल किए जाने वाले आवासों की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए इसे वैध करना अपेक्षित है। महाराष्ट्र के पालघर के शहरी क्षेत्रों के लिए, 1,13,351 आवासों के लिए मांग पंजीकृत की गई है जिसमें से दिनांक 25.11.2019 की स्थिति के अनुसार 85,461 आवासों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ख) लाभार्थियों की संख्या का जिला- वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है ।

अनुलग्नक

दिनांक 05.12.2019 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2944 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई (यू) के तहत महाराष्ट्र राज्य में पालघर सहित लाभार्थियों के लिए स्वीकृत आवासों का जिला- वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वीकृत आवासों की संख्या
1	अहमदनगर	15,142
2	अकोला	11,011
3	अमरावती	14,206
4	औरंगाबाद	15,416
5	बीड	10,644
6	भंडारा	2,828
7	बुलढाणा	5,411
8	चंद्रपुर	6,282
9	धुले	3,635
10	गडचिरोली	1,696
11	गोंदिया जिला	3,771
12	हिंगोली	4,283
13	जलगांव	17,846
14	जालना	8,988
15	कोल्हापुर	6,949
16	लातूर	8,650
17	मुंबई	6,295
18	मुंबई (उपनगरीय)	2,05,613
19	नागपुर	56,840
20	नांदेड़	19,971
21	नंदुरबार	1,651
22	नासिक	38,464

23	उस्मानाबाद	9,612
24	पालघर	85,461
25	परभनी	11,140
26	पुणे	1,51,383
27	रायगढ	63,152
28	रत्नागिरी	2,244
29	सांगली	5,715
30	सतारा	9,857
31	सिंधुदुर्ग	687
32	सोलापुर	59,444
33	ठाणे	2,60,785
34	वर्धा	7,795
35	वाशिम	2,193
36	यवतमाल	14,885
कुल* :-		<b>11,50,073</b>

\*पीएमएवाई (यू) के सीएलएसएस घटक के तहत 128 लाभार्थियों को संवितरण के लिए सीएनए को हाल ही में जारी ब्याज सब्सिडी सहित ।